



2026:AHC:163348

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7906

वर्ष 2026

विंदा देवी

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दया शंकर पाण्डेय, प्राची त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 288/2021 भादसं की धारा 304, 504; थाना तार्या सुजान, जिला कुशीनगर में आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत की मांग के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है; कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आवेदक एक महिला है और इससे पहले इस न्यायालय की एक पीठ ने दं.प्र.सं. की धारा 438 के तहत दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 3595/2022 में 19.05.2022 के आदेश से उसे अग्रिम जमानत दी थी। अधिवक्ता ने 19.05.2022 के उस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश की प्रतिलिपि पेश की है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि इस मामले में 18.09.2022 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था और संबंधित न्यायालय ने 22.11.2022 के आदेश से अपराध का संज्ञान लिया था। आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1** मामले में तय किए गए विधि को देखते हुए, आवेदक को विचारण खत्म होने तक अग्रिम ज़मानत मिलनी चाहिए। प्राथमिकी में आवेदक की भूमिका सामान्य बताई गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आखिर में, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देती है और जब भी संबंधित न्यायालय बुलाएगी, वह पेश होगी। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम ज़मानत मिलती है, तो वह ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी, मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगी।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, वे तथ्यों से जुड़ी बातों पर कोई विवाद नहीं करते हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने हैं और अभिलेख देखे हैं।

6. इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल की जा चुकी है और आवेदक पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने जाँच में सहयोग नहीं किया। आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है।

7. **अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई, (2022) 13 एससीसी 764** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि:

"11. ऊपर बताई गई बातों से पता चलता है कि दंप्रस की धारा 170 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते समय दंडाधिकारी के लिए यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जिस दंडाधिकारी या न्यायालय को मामले का संज्ञान लेने या आरोपी पर मुकदमा चलाने का अधिकार है, उसे तुरंत आरोपपत्र स्वीकार करना होगा और दंप्रस की धारा 173 के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यह सही कहा गया है कि ऐसे मामले में दंडाधिकारी या न्यायालय को हमेशा समन जारी करना चाहिए, न कि गिरफ्तारी वारंट। अगर वह गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अपने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे दंप्रसं की धारा 87 के तहत कारण दर्ज करने होंगे कि आरोपी या तो फरार है या समन का पालन नहीं करेगा या समन की उचित तामील का साक्ष्य होने के बावजूद पेश होने से इनकार कर दिया है। असल में, उच्च न्यायालय की उप-धारा (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी बरतने के बारे में हैं।

12. जहाँ तक मौजूदा मामले और दंप्रसं की धारा 170 के तहत सामान्य सिद्धांतों का सवाल है, सबसे उपयुक्त टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय के निर्णय की उप-धारा (v) में हैं। यह उन मामलों के संदर्भ में है जहाँ आरोपी पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है, लेकिन जांच के दौरान उसकी हिरासत की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी स्थिति में, आरोपी को ज़मानत पर रिहा करना उचित है क्योंकि जांच के दौरान उसकी गिरफ्तारी न होना या उसे हिरासत में पेश न किया जाना ही उसे ज़मानत पर रिहा होने का हकदार बनाता है। इसके पीछे का तर्क स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कई सालों से आज़ाद है और जांच के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो सिर्फ इसलिए कि चार्ज-शीट दाखिल हो गई है, अचानक उसकी गिरफ्तारी और जेल भेजने का आदेश देना ज़मानत देने के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ होगा। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं।"

8. इसलिए, अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के अधिवाक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में, यह मामला आवेदक को मामले में विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है।

9. तदनुसार, अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) अगर आवेदक - विंदा देवी, जो ऊपर बताए गए मामले में शामिल हैं, को गिरफ्तार किया जाता है या वह पेश होती हैं, तो उन्हें विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानती देने होंगे।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेंगी और निष्पक्ष विचारण के लिए जब भी ज़रूरत होगी, संबंधित न्यायालय में पेश होंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देंगी जिससे वह व्यक्ति न्यायालय के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग होने पर, लोक अभियोजक/जांच अधिकारी/शिकायतकर्ता को यह अधिकार है कि वे संबंधित न्यायालय में आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर कर सकें।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

5 अगस्त, 2026

ए. पी. पाण्डेय